



जाने माने मूर्तिकार बोगदान बोगदानोविच की रचना, तस्वीर में नजर आ रहा विशालकाय स्टोन प्लॉवर विश्व विख्यात है। क्रोएशिया के जसेनवैक शहर में इस स्मारक को देखने दुनियाभर से पर्यटक आते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान इसी स्थान पर बने यातना शिविर में मारे गए थे। सन् 1966 में बनकर तैयार हुए सीमेंट के इस फूल की पांच पंखुड़ियाँ जसेनवैक यातना शिविर के बंदियों को समर्पित हैं। अन्य यातना शिविरों के विपरीत इस यातना शिविर का नियंत्रण नाज़ियों के हाथ में नहीं था, बल्कि क्रोएशिया की सरकार के हाथ में था जो उस समय नाज़ियों के साथ थी। यह यूरोप के सबसे बड़े यातना शिविरों में से एक था। यह तो पता नहीं है कि, यहां कितने लोग मारे गए, लेकिन तकरीबन 8 लाख लोगों को यहाँ पर यातनाएं दी गई थीं। इनमें से अधिकांश सर्बिया के लोग थे, जिन्हें "यूयोर" (विशुद्ध) क्रोएशिया के निर्माण के लिए मारा गया। यह भायाव कैम्प 1945 में बंद हुआ और उसके बाद पूर्व युद्ध बंदियों ने इसे जला दिया। स्टोन प्लावर के नीचे एक मकबरा भी है, जहां पीड़ितों के अवशेष हैं। इसका निचला भाग खुला हुआ है, जहाँ से लोग स्मारक के अंदर जाकर मृतकों को याद करते हैं।

## झारखण्ड के अधिकारियों व भाजपा सांसदों ने एक दूसरे पर एफ.आई.दर्ज करवाई

देवघर/ नई दिल्ली, 3 सितम्बर झारखण्ड पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में संध लगाने के आरोप में भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके दो बेटों, सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक समेत नौ लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है। इन सभी पर देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) रूम में जबनर घुसने का आरोप है। सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद की शिकायत पर एक सितंबर को कुंडा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया कि उक्त व्यक्तियों ने जबनर ए.टी.सी. कक्ष में प्रवेश करके कई सुरक्षा मानकों उल्लंघन किया और अधिकारियों पर टेक-ऑफ करने के लिए दबाव डाला। शिकायत पत्र में सभी पर दबाव बनाकर जबनर ए.टी.सी. क्लियरेंस लेने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में भाजपा सांसद ने भी दिल्ली में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।

■ झारखण्ड में दो भाजपा सांसदों सहित नौ लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

■ भाजपा सांसदों ने दिल्ली पहुंचते ही झारखण्ड के अधिकारियों के खिलाफ अभद्रता और गाली-गलौज की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई।

■ मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे, दुमका छात्रा हत्याकांड मामले में परिजनों से मिलने चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से शाम छह बजे तक ही उड़ान की इजाजत थी, लेकिन सांसदों पर जबनर शाम पांच बजकर 30 मिनट पर एयर ट्रैफिक क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है।

■ इस घटना के बाद ही झारखण्ड के अधिकारी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाई।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने देवघर डीसी मंजूनाथ और झारखंड पुलिस के खिलाफ नॉर्थ एवैन्यू थाने में जीरो

धमकी दी।

गौरतलब है कि, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे दुमका छात्रा हत्याकांड मामले में परिजनों से मिलने चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से शाम छह बजे तक ही उड़ान की इजाजत थी लेकिन सांसद पर जबनर शाम पांच बजकर 30 मिनट पर क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद ही अधिकारी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है।

कुंडा (झारखण्ड) थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि, दोनों सांसदों - निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी - और हवाई अड्डे के निदेशक सहित नौ लोगों पर आई.पी.सी. की धारा 336 (दूसरा) की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 447 (आपराधिक अतिचार के लिए सजा), 448 (घर-अतिचार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

## मैक्सिको में फुटबॉल ग्राउण्ड में गोलीबारी, 4 की मौत

मैक्सिको सिटी, 3 सितम्बर (वार्ता)। मैक्सिको के मध्य प्रांत मोरेलोस में एक फुटबॉल मैच में सशस्त्र संदिग्धों ने गोलीबारी की, जिसमें एक पूर्व मेयर सहित कम से कम चार लोग मारे गए हैं।

यह जानकारी स्थानीय अभियोजक का कार्यालय ने दी। कार्यालय के मुताबिक गोलीबारी स्थानीय समानानुसार गुरुवार (अंतर्राष्ट्रीय समय के मुताबिक शुक्रवार को तड़के 2.15 बजे) पर येकापिक्वला शहर में हुई। कार्यालय के

■ सशस्त्र हमलावरों ने ग्राउण्ड में घुसकर लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

अनुसार सशस्त्र संदिग्ध आए और वहां मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।

इस घटना में येकापिक्वटला के पूर्व मेयर रिफ्यूजियो अमारो लुना सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि इस घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मैक्सिको के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मोरेलोस में हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। यह प्रांत अपहरण की घटनाओं के मामले में देश में पहले स्थान पर है।

## नॉर्थ ईस्ट में नीतीश की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा के 49 विधायक हो गए हैं। जद (यू) के 9 पार्षदों में से 8 भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब कुल 20 पार्षदों में से भाजपा के 18 पार्षद हो गए हैं। इसके अलावा जद (यू) के 18 जिला परिषद सदस्यों में से 17 ने भाजपा जाईन कर ली है। अब कुल 241 जिला परिषद सदस्यों में से भाजपा के 206 सदस्य हैं। इसके अलावा जद (यू) के 119 ग्राम पंचायत सदस्यों में से सौ से अधिक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब कुल 8 हजार 332 ग्राम पंचायत सदस्यों में से भाजपा के करीब 6 हजार 530 सदस्य हैं।

ये नवीनतम घटनाक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार का शासन चलाने के लिए एक "महागठबंधन" का गठन करने को लेकर भाजपा को तिलांजलि देकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस व अन्य पार्टियों से हाथ मिलाते के कई हफ्तों बाद सामने आए हैं।

इस घटनाक्रम से वाकिफ लोगों का कहना है कि बिहार में हाल ही में जो कुछ हुआ है, उसके बाद भाजपा ने जद (यू) पर पलटवार करने का निर्णय ले लिया है। वर्ष 2020 में भाजपा-जद

(यू) ने एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार बनाई थी।

क्षेत्रीय पार्टियों में यह भय घर कर गया कि विपक्ष अभी भाजपा का मुकाबला नहीं करेगा तो उसका वही हथ्र होगा, जो महाराष्ट्र में शिवसेना का और मणिपुर में जद (यू) का हुआ है। भाजपा बिहार में भी नीतीश कुमार के निकट सहयोगी रहे आए.सी.पी. सिंह की सहायता से जद (यू) में विभाजन की कोशिश करती रही है। टी.एम.सी., टी.आर.एस. और आप जैसे कई क्षेत्रीय पार्टियां जहां कांग्रेस के विपक्ष के मोर्चे के नेतृत्व करने के खिलाफ हैं, वहां बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, के.सी.आर. राव और अरविन्द केजरीवाल के नीतीश कुमार के साथ मित्रवत संबंध हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेतृत्व ने गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट करने का काम नीतीश पर छोड़ने का निर्णय लिया है और वह स्वयं संगठन को मजबूत कर और जनता के साथ पुनः सम्पर्क स्थापित कर पार्टी को पुनर्जीवित होने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

## सिब्वल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत के काम-काज की आपराधिक अवमानना प्रक्रिया शुरू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

कन्स्ट्रैट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 15 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के लिये यह शर्त है कि उसके लिये अर्दनी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की स्वीकृति होनी चाहिए।

अर्दनी जनरल ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कुछ फैसलों की समीक्षाओं से संबंधित बयान साफतौर पर निष्पक्ष टिप्पणी की सीमा में आते हैं, जिसकी कन्स्ट्रैट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 5 के अनुसार अनुमति दी है।" उन्होंने कहा कि सिब्वल ने पी.एम.एल.ए. (पीवेंशन ऑफ मन-लॉन्डरिंग एक्ट) की आलोचना की थी, जिस पर पुनर्विचार करने का निर्णय बाद में स्वयं अदालत ने ही ले लिया था।

के पूरे भाषण को अच्छी तरह सुनने-समझने के बाद, मुझे लगता है कि अदालत और इसके फैसलों की आलोचना इस प्रकार की थी कि अदालत उसका उपयोग न्यायिक व्यवस्था के हित में कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं लगता कि संबंधित बयानों का उद्देश्य अदालत पर लांछन लगाना या न्यायपालिका को कॉन्फिडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्ट की प्रभावित करना था।

## रक्षा रत्नों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा इनके पास, जमीन जैसी विशाल परिसम्पत्तियां हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन प्रधानमंत्री संभवतः अपने खास दोस्त एवं अन्य लोगों को उपकृत करना चाहते हैं।" संभवतः, इनकी जमीन उनके मित्रों के लिये, पैसा बनाने की दृष्टि से, बहुत हितकर है।

# चीन ने आई.एन.एस. विक्रांत की नौसेना को सुपर्दगी पर भारत की खिल्ली उड़ाई

## चीन के सरकारी मीडिया ने कहा, भारत पहले अपने लोगों की गरीबी दूर करने पर ध्यान दे

नई दिल्ली, 3 सितम्बर चीन शायद पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमानवाहक पोत आई.एन.एस. विक्रांत पर भारत की सफलता से खुश नहीं है। वही कारण है कि पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना कर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। बाद में उसने अपना स्टैंड बदलते हुए पश्चिमी देशों को लेकर भारत को समझाइश दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत को पश्चिम देशों की चापलूसी से सतक रहना चाहिए। इस लेख में चीनी मीडिया ने कहा कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आई.एन.एस. विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। वे भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता के बीच चीन को लेकर एक राय कायम होगी और सरकार पर बीजिंग विरोधी फैसले लेने का दबाव बढ़ेगा।

■ चीन के सरकारी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, भारत पश्चिमी देशों की चापलूसी और झांसे में ना आये। चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है, वह अपने लोगों की सलामती पर ध्यान केन्द्रित करे।

■ ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि, पश्चिमी देश भारत के लोगों को भड़काना चाहते हैं, इससे उनके मन में चीन के खिलाफ बैर पनपेगा और सरकार पर बीजिंग के खिलाफ फैसले लेने का दबाव बनेगा।

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत के शुक्रवार को कमीशनिंग को पश्चिमी मीडिया से काफी प्रशंसा मिली। सी.एन.एन. की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमानवाहक पोत ने भारत को दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक कुलीन लीग में डाल दिया है। न्यूज एजेंसी ए.एफ.पी. ने एक लेख में इसे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के सरकारी प्रयासों में एक मील का पथर

बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत के पहले धरेलू विमानवाहक के प्रमुख लक्ष्य के रूप में "चीन के बहुत बड़े और बढ़ते बेड़े" को प्रस्तुत कर, वे चीन और भारत के बीच तनाव और यहां तक कि टकराव को भड़काना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वह वास्तव में भारत के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में अपनी प्रगति का जश्न मनाने का क्षण था। आई.एन.एस. विक्रांत का निर्माण भारत के लिए आसान नहीं रहा है। कोचीन शिपयार्ड में

धूमधाम से आयोजित किए गए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी विमानवाहक पोत को 2009 में बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें 13 साल लगे गए उन्होंने भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कोच्चि में नौसेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके देश ने एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

ग्लोबल टाइम्स ने सवाल किया कि, लेकिन क्या पश्चिम भारत के लिए वाकई खुश था? प्रधानमंत्री मोदी ने कमीशन समारोह में भारत के औपनिवेशिक युग से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतीक के बिना देश के नए नौसैनिक ध्वज को भी फहराया। हालांकि, अधिकांश पश्चिमी रिपोर्टों में इसका शायद ही कभी उल्लेख किया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने समझाइश देते हुए कहा कि भारत को पश्चिम की इस उकसावे को चीन के खिलाफ किसी सैन्य घटना में बदलने से बचना चाहिए।

## चिटफंड घोटाले में टी.एम.सी. नेता गिरफ्तार

कोलकाता, 3 सितंबर (वार्ता)। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने गुणमूल कांग्रेस नेता एवं हलीशहर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू सहानी को कथित चिटफंड घोटाखाड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सहानी को शनिवार को आसनसोल की सी.बी.आई. अदालत में पेश किया जाएगा। सी.बी.आई. की एक टीम ने सहानी को उत्तर 24 परगना में उनके हलीशहर स्थित घर से गिरफ्तार किया। उनके घर से 80 लाख रुपये नकद, पांच कारतूस के साथ एक बन्दूक और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गये।

सी.बी.आई. ने सहानी को शुक्रवार रात अक्टूबर 2018 में चिटफंड घोटाखाड़ी को लेकर दर्ज मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया था। उन पर समग्र वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन नामक कंपनी के फंड की हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया गया है।

## श्रीलंका के भगौड़े पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे स्वदेश लौटे

### राजपक्षे दो महीने पहले आर्थिक संकट के खिलाफ जन विद्रोह के बाद देश छोड़कर भाग गये थे

कोलंबो, 3 सितंबर (वार्ता)। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के खिलाफ जन विद्रोह के बाद देश छोड़कर भाग जाने के दो महीने से भी कम समय में स्वदेश लौट आए हैं।

'डेली मिरर' अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राजपक्षे (73) शुक्रवार को श्रीलंका लौटे। वह करीब सात हफ्ते बाद श्रीलंका वापस आए हैं। जुलाई में वह आर्थिक संकट की वजह से लोगों के उग्र प्रदर्शनों के देखते हुए देश छोड़कर भाग गए थे। वह भंडारनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे। मंत्रियों और राजनेताओं के स्वागत दल ने राजपक्षे को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वह बैंकॉक से सिंगापूर होते हुए स्वदेश लौटे हैं।

■ पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे कोलंबो में एक राजकीय बंगले में रहेंगे। जिस क्षेत्र में राजपक्षे रहेंगे, उस क्षेत्र की सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा सुरक्षा दल तैनात किया जाएगा। राजपक्षे जुलाई में भागकर मालदीव और सिंगापूर पहुंचे थे।

पूर्व राष्ट्रपति कोलंबो में एक राजकीय बंगले में रहेंगे। जिस क्षेत्र में राजपक्षे रहेंगे, उस क्षेत्र सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा सुरक्षा दल तैनात किया जाएगा। राजपक्षे जुलाई में मालदीव और सिंगापूर भागकर पहुंचे थे। सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेराव भवन और दो अन्य प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद नौ जुलाई को वह श्रीलंका से भाग

गए थे। सिंगापूर सरकार द्वारा तीसरी बार उनके वीजा का विस्तार देने से मना करने पर वह थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। दैनिक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजपक्षे तब तक कोलंबो में रहेंगे जब तक कि अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए उनके आवेदन को मंजूरी नहीं मिल जाती। रिपोर्ट में कहा गया है, "राजपक्षे को एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में सभी विशेषाधिकार दिए जाएंगे।"

## ‘ऐसा हुआ तो एम्स की प्रतिष्ठा, मान्यता और पहचान खत्म हो जायेगी’

### एम्स दिल्ली की फैकल्टी एसोसिएशन ने देश के सभी 23 एम्स संस्थानों का नाम बदलने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का भारी विरोध शुरू किया

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। ऑल इण्डिया मैडिकल साइन्सेज (एम्स) दिल्ली की फैकल्टी एसोसिएशन ने देश के सभी 23 एम्स को विशिष्ट नाम देने के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया है और इस मुद्दे पर अपने सदस्यों की राय मांगी है।

एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि, इस प्रस्ताव पर अमल से संस्थान की पहचान एवं प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी।

सदस्यों के बीच प्रसारित एक नोट में एसोसिएशन ने कहा है कि, पहचान नाम से जुड़ी होती है और अगर पहचान खो जाती है तो देश के भीतर और बाहर संस्थागत मान्यता भी खो जाती है। यही कारण है कि, ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज और हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का नाम सदियों से एक ही है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अचल कुमार श्रीवास्तव और महासचिव डॉ. हर्षल

■ एसोसिएशन ने कहा, "पहचान नाम से जुड़ी होती है और अगर पहचान खो जाती है तो देश के भीतर और बाहर संस्थागत मान्यता भी खो जाती है। यही कारण है कि, ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज और हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का नाम सदियों से एक ही है।"

रमेश साल्वे के दस्ताख्त वाले नोट के मुताबिक, भारत में आई.आई.टी. (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) की पहचान उनके नाम से है, जो उन्हें एक संस्थान को पहचान देती है और इसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई.आई.एम. के मामले में भी ऐसा ही है।

इसमें लिखा है कि, नाम पर आधारित पहचान कितनी मजबूत होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के नाम पर शहरों में स्थित हैं, उनका नाम बदलकर

कोलकाता, मुंबई और चेन्नई किया जा चुका है। अगर नाम बदल दिया जाता है तो एम्स दिल्ली को पहचान और मनोबल की भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को भी प्रभावित करेगा।

उल्लेखनीय है कि, पिछले दिनों यह सामने आया था कि सरकार ने दिल्ली सहित अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के नाम पर शहरों में स्थित हैं, उनका नाम बदलकर

## ‘अगर अमेरिका ने ताईवान को...

पैटगोन ने कहा कि सैन्य उपकरण देने और रक्षा सहयोग से क्षेत्र का मूल सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इससे ताईवान के प्रति हमारी नीति में कोई बदलाव परिलक्षित नहीं होता है।

राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने कहा कि यह पैकेज कुछ समय से विचारधीन था और इसे ताईवान व अमेरिकी सांसदों के साथ विचार-विमर्श के बाद विकसित किया गया है।

वाइट हाउस में चीन और ताईवान मामलों की सीनियर डायरेक्टर लौरा रोसेनबर्ग ने एक बयान में कहा कि "चीफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताईवान के इर्द-गिर्द कठोर हवाई और समुद्री कार्रवाई करने सहित अपना दबाव बढ़ाना जारी रखे हुए है और ताईवान जलडमरूमध्य की यथा स्थिति बदलने के प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम ताईवान को वे चीजे उपलब्ध करा रहे हैं जिनकी उसे अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए जरूरत है।"

क्षेत्र में संयुक्त रूप से शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेंगे।

यू.एस.-ताईवान बिजनैस काउन्सिल के प्रेसिडेंट रूफर्ट हर्मान-चेम्बर्स ने कहा कि ताईवान को हथियारों की बिक्री में "सीमित रूप" रखने का उनके संघटन ने विरोध किया था। चेम्बर्स ने एक बयान में कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) ने हाल ही में कलकत्ता की रक्षा के लिए अमेरिका के निरंतर सहयोग को दर्शाती है क्योंकि ताइपे चीन के दबाव का सामना कर रहा है। चीन का दावा है कि ताईवान उसके देश का हिस्सा है और उसने इस लोकतांत्रिक देश को अपने नियंत्रण में लाने

के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी इंकार नहीं किया है।

हथियारों की बिक्री को कांग्रेस द्वारा समीक्षा की जाएगी, लेकिन कांग्रेस के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन साधियों ने बताया कि उन्हें इस पर किसी विरोध की उम्मीद नहीं है। पेलोसी की ताईवान यात्रा के बाद दोनों पार्टियों के सांसदों के साथ ही अमेरिकी राज्यों के गवर्नर वहां के कम से कम दो या अधिक दौरें कर चुके हैं और बीजिंग ने इन सभी की भर्त्सना की है।

## ‘शबाना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आर.एस.एस. के शीर्ष नेतृत्व ने मिश्रा जैसे दूसरी पंक्ति के नेताओं को अभद्र तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से न तो कभी रोकने की कोशिश की है और न कभी ऐसे कुलों की निन्दा की है, जिससे यह सन्देश जाता है कि इस प्रकार के आचरण-व्यवहार को उसकी स्वीकृति है।

## ‘केस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

द्वारा तत्कालीन सी.जे.आई. दीपक मिश्रा के खिलाफ 12 जनवरी, 2018 को आयोजित की गई एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन जजों ने केसों की लिस्टिंग की समस्या पर भी जोर दिया था। इससे जाहिर होता है कि इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन चारों जजों, जो अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, के नाम हैं-पूर्व सी.जे.आई. रमन गोगोई तथा न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेस्वर, मदन लोकर तथा कुरियन जोसेफ।

शुक्रवार शाम को बी.सी.आई. द्वारा सी.जे.आई. को बधाई देने के लिये आयोजित किये गये एक समारोह में, वरिष्ठ एडवोकेट मिश्रा ने कहा, "सी.जे.आई. ललित ने मुकदमों की लिस्टिंग में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है, जिससे कि वकीलों को परेशानी ना हो।

आज, जब कैस टायर होते हैं, तो वे सुनवाई के लिये अगले दिन ही पूंचीबद्ध कर दिये जाते हैं। यह सी.जे.आई. ललित का नियम है। गुरुवार को, जब मैं न्यायालय में था, उन्होंने 200 उल्लेखित केसों पर विचार किया था।"

सी.जे.आई. की सेवानिवृत्ति से पहले के उनके 74 दिन के संक्षिप्त कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि काफी की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, कार्यकाल की लम्बाई नहीं। उन्होंने इस समारोह में यह घोषणा भी की कि बी.सी.आई. शनिवार को सभी राज्यों की बार एसोसिएशनों की एक मीटिंग बुला रही है तथा इस मीटिंग में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाये जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जायेगा।

## केन्द्र व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टी. के आंकड़े ट्वीट कर दावा किया कि तेलंगाना ने टैक्स के रूप में जितनी राशि उत्पादित की, उसे उसका आधा ही प्राप्त हुआ। अब राशन की दुकान की घटना ने जो काम किया है, वह है राज्य और केन्द्र सरकार के बीच वाक्य युद्ध तेज करना और अब बात आर्थिक प्रदर्शन पर शिफ्ट हो गई है, जिसमें लगता है कि राज्य सरकार मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव अर्थव्यवस्था को लेकर केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते रहे हैं और कीमत वृद्धि, महंगाई तथा रूपए के गिरते मूल्य पर सवाल उठाते हैं। वे केन्द्र सरकार के प्रदर्शन को लेकर एक कथानक बना रहे हैं। यह आभास होने के बाद कि भाजपा अब उनके खुद के गद्द पर हमला बोल रही है, के.सी.आर. ने भाजपा और केन्द्र सरकार के खिलाफ पूर्ण हमला बोल दिया है। वे उसे चिढ़ाने के लिए गुजरात मॉडल को एक विफल मॉडल बताते हैं। तेलंगाना में दिसम्बर 2023 से पूर्व विधानसभा चुनाव होने हैं।